Failure of the Scheme to Generate Money for Housing Sector

*104. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the scheme to mop up black money and its investment in the housing sector has failed ;

(b) if so, the total amount generated by this scheme during the last one year ; and

(c) what further steps Government propose to take to generate money for housing sector in the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) National Housing Bank (Voluntary Deposits) Scheme, 1991 was launched on October 1, 1991 and closed on January 31, 1992. The amount collected under the scheme was Rs. 150.21 crores. No targets for collection under the Scheme were made.

(c) Reserve Bank of India (RBI) makes annual credit allocation to the commercial banks for lending to the housing sector. The Banks are required to lend 1.5% of their incremental deposits of the current year over that of the previous year to the housing sector. The amount allocated for the banking sector for financing housing was Rs. 150 crores in the year 1987, Rs. 225 crores in 1988, Rs. 322 crores in 1989-90 and Rs. 387 crores in 1990-91.

National Housing Bank (NHB) provides financial assistance to all eligible primary lenders *viz.*, Scheduled Commercial and Cooperative Banks, Housing Finance Companies, Apex Cooperative Housing Finance Societies and State Cooperative Land Development Banks. The total finance provided stood at Rs. 568 crores as at the end of June, 1991 as compared to Rs. 132 crores in June, 1990. NHB is also operating since July, 1989 through the scheduled commercial banks and select housing finance companies, their Home Loan Accounts (HLA) Scheme under which deposits are made by individuals. Till 31st January, 1992 Rs. 107.26 crores were deposited in 5.56 lakh accounts.

श्री गुफरान आजम : सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि अरबन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ एलोकेशन आफ बजट का कहा, उस पर 1 जुलाई, 1991 को माननीय वित्त मंत्री जी ने एक स्कीम बनाई—नेशनल डेवलपमेंट फंड—और यह कहा कि ब्लैक मनी को मोप अप करने के लिए एच० एच० बी० में पैसा जमा होगा और जैसी मेरी जानकारी है कि यह स्कीम तकरीबन फेल हो गई और ब्लैक मनी ज्यादा जमा नहीं हो सकी ? तो क्या उस वजह से अरबन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की जो स्कीम है हाउसिंग के लिए, वह भी फेल हो जाएगी ?

श्री दलबीर सिंह : सभापति महोदय, (व्यवधान)

श्री अजीत जोगी : वित्त मंत्री जी जवाब दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

एक माननीय सदस्य: आपका प्रश्न नहीं है, वित्त मंत्री जी जवाब दें ।

श्री सभापति : कोई भी जवाब दे सकता है। (व्यवधान)

श्री दलबीर सिंह : जहां तक यह योजना थी, वालेंटरी डिपाजिट स्कीम थी, इसके तहत 150.21 करोड़ रूपए इसमें आए, लगभग 60 करोड़ रु० हमको इसमें मिले और जो माननीय सदस्य ने कहा है जितनी उम्मीद थी उतनी राशि तो नहीं मिली लेकिन इसके तहत हमने जो राष्ट्रीय आवास बैंक है, उसको कहा है और जैसी कि नीति थी कि अरबन, स्लम्स और ग्रामीण अंचलों में सस्ते मकान बनाएंगे, इसके लिए गाइडलाइन्स बना रहे हैं और इसको जल्दी से हम इम्लीमेंट कराना चाहते हैं ।

श्री शुकरान आजम : सभापति जी, क्या माननीय मंत्री जी ने कहा कि ब्लैक मनी इकट्ठी नहीं हो सकी, तो क्या माननीय मंत्री जी, देश में जो ब्लैक मनी इकट्ठी करते हैं उनसे प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा ब्लैक मनी इकट्ठी करो ताकि हम अरबन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को दें अगर ऐसा नहीं है तो कितना एलोकेशन करने जा रहे हैं ?

श्री दलबीर सिंह : सर, जहां तक हाऊसिंग का सवाल है मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसके लिए जो बजट होता है सेंट्रल सैक्टर का और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने बजट में प्रावधान करती हैं लेकिन इंक्रिमेंटल डिपाजिट का जो 1.5 परसेंट यहाँ पर है, उसमें से सिर्फ 30 परसेंट डायरेक्ट कार्मशियल बैंक लैडिंग करते है और 70 परसेंट में से 30 परसेंट जो होता है विभिन्न एजेंसियों जैसे कोआपरेटिव सैक्टर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वित्तीय कंपनियां हैं, इनके तहत होता है और जो 40 परसेंट बचता है वह जो हमारा राष्ट्रीय आवास बैंक है, हुडको है, उसको हम देते हैं । इतना ही नहीं हाउसिंग सैक्टर के लिए जनरेट करने के लिए एल. आई. सी. और जी० आई. सी. से पैसा मिलता है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने बैंकिंग सैक्टर से जो पैसा दिया है यह 1987 में 150 करोड़ रुपए दिया है, 1988 में 225 करोड़ रूपए, 1989-90 में 332 करोड़ रूपए और 1990-91 में 337 करोड़ रूपए दिया है इसके अलावा जो राष्ट्रीय आवास बैंक बना है, जो 1989 से कार्य कर रहा है, उसमें भी जब से वह काम करना शुरू हुआ है, अब तक 568 करोड़ रुपए आवास के लिए दिए जा चुके हैं ।

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : Sir, housing has been recognised as a very important activity. Besides providing housing, it provides the scope for large employment. I would like to know, Sir, whether the Government has drawn up annual schemes under which this activity is taken up. If so, what was the total amount of money given last year, that is, during 1990-91, and what is the money that is going to be given for the housing activity in the current year ?

श्री दलबीर सिंह : सर, माननीय सदस्य ने जो पूछा है मूल प्रश्न, वह अर्बन डैवलपमेंट मिनिस्ट्री से संबंधित है । अगर वह पूछना चाहें तो सैपरेट नोटिस देकर पूछ सकते हैं लेकिन जहां तक ऐलोकेशन का सवाल है अभी मेरे पास फिगर्स नहीं हैं, मैं माननीय सदस्य को बाद में भेज दूंगा लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसके साथ-साथ एल. आई. सी, और जी. आई. सी. को जो राशि आवंटित की है वह मैं बताता हूं । 1989 में 353.10 करोड़ 1989-90 में 515.54 करोड़ 1990-91 में 825.17 करोड़ और 1991 में 1066 करोड़ इसी तरह से जी. आई. सी. से भी हमने दिया है– 62.30 करोड़ 73.80 करोड़ और 81.70 करोड़, यह हाऊसिंग सैक्टर को दिया है । और भी जो स्टेट गर्वनमेंट में कोआपरेटिव सैक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीटयूशंस हैं और उसके साथ-साथ बैंकिंग सैक्टर का हमारा पैसा है वह हम दे रहे हैं ।

SHRI JAGESH DESAI : Mr. Chairman, Sir, we have witnessed so many voluntary disclosure schemes, and this scheme is an utter failure. For the first time, the amount received is only Rs. 60 crores by way of tax. Why has this happened ? It was the wrong timing of the launching of the scheme. They launched both the schemes, the amnesty scheme under foreign remittances and this housing scheme at the same time. At that time, Sir, dollar was available by paying only 15 per cent premium whereas one has to pay 40 per cent in the scheme. And that is why those who wanted to deposit their black money, they preferred that voluntary amnesty scheme under foreign remittances. That is why people did not deposit in this scheme. And it was a wrong-timing. And only Rs. 60 crores has been received from this scheme by way of tax. In this connection, I would like to

say that you are giving one and a half per cent on incremental deposit of the earlier year. But, the inflation rate is 13 per cent. So, there is not at all any increment as far as the deposits are concerned. Instead of Rs. 60,000 crores, it is only Rs. 65,000 crores. And only on Rs. 5,000 crores they have got this money. And now, because of mutual funds, deposits are not coming to the banks. People are depositing in the mutual funds. As such, the incremental deposit is going to come down. So, I would like to know from the Government whether they are going to increase this percentage of 1.5 per cent to 3 per cent so that there will be enough funds for the purpose of housing. The Finance Minister is sitting here. I would like to know whether he is going to give more resources for the purpose of housing or not.

श्री दलबीर सिंह : सर, जहां तक योजनाओं का संबंध है, अच्छे के लिए सोचा जाता है । हमने तो सोचा था कि इसमें ज्यादा पैसा आएगा ताकि हाऊसिंग सैक्टर पर हम ज्यादा पैसा दे सकेंगे खासकर अर्बन स्लम्स के लिए और खासकर गरीब लोगों के मकान के लिए और जहां तक माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, इसका जो इंक्रीमेंटल है । 1.5 परसेंट, इसके बारे में उन्होंने जो सजेशन दिया है, उस पर भी हम विचार करेंगे और उसके साथ-साथ मैंने बतलाया है कि सन् 1987 से लगातार हम हाऊसिंग सैक्टर के लिए वृद्धि कर रहे हैं और पैसा काफी तादाद में मिला है और इतना ही नहीं राष्ट्रीय आवास बैंक में खुद हौम लोन एकाउंटस 1989 से खोले गए हैं । इसमें देश के लगभग 5 लाख से ऊपर खाताधारी हैं और 107 करोड़ रुपए इसमें आए हैं और यदि कोई इंडिविज्युल अपना मकान बनाने के लिए कर्ज लेना चाहेगा तो पांच गुना उसमें से पैसा ले सकता है और मकान का निर्माण कर सकता है ।

श्री विट्ठलभाई पटेल : सभापति जी, आज से 4-5 साल पहले जब एडवर्ड फलेरो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस हाऊस में कहा था कि व्यक्तिगत नागरिक को मकान बनाने के लिए या मकान खरीदने के लिए बैंक लोन देगी लेकिन जब बैंक के अफसरों के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई रिजर्व बैंक का आदेश नहीं है । मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसके बारे में व्यक्तिगत नागरिकों को अगर मकान बनाने के लिए या मकान खरीदने के लिए आदेश नहीं दिए हों तो दे देंगे और क्या करना चाहते हैं व्यक्तिगत नागरिक के लिए ?

श्री दलबीर सिंह : मैंने पहले भी उत्तर में बताया है कि जहां तक इंक्रिमेंटल डिपाजिट का सवाल है, उसमें से कोई इग्नोर नहीं कर सकता और जैसा मैंने बतलाया कि राष्ट्रीय आवास बैंक में खुद इंडिविज्युल्स के लिए एकाउंट्स हैं और उसमें वे खुद राशि जमा करते हैं और उसका पांच गुना वे प्राप्त कर सकते हैं । तो ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक उनको इग्नोर करता है ।

*105. [*The questioner* (SHRI SURESH PACHOURI) *was absent. For answer, vide Col. .... infra.*]

Surplus Stock of Rice and its Export to Cuba

*106. SHRI KAPIL VERMA :†
SHRI ASHOK NATH VERMA :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government have, presently, adequate surplus stock of rice to enable it to export to Cubo as requested by them ; and

(b) what is the rough estimate of rice production and internal consumption ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM) : (a) The Government have stocks of rice which are considered adequate to meet the reasonable requirements of the Public Distribution System (PDS). In so far as export of rice to Cuba is concerned, the matter is under consideration of the Government.

*[The question was actually asked on the floor of the House by Shri Kapil Verma].